

Asian Culture
B.A. Semester II
Paper I : South Asia (1870-1919)

Department of Western History
University of Lucknow

(Course Instructor: Prof. Abha Trivedi)

India under Edward Robert Bulwer, Lord of Lytton (1876-1880) :

- Lytton was sent to India by Conservative government of Benjamin Disraeli in 1876.
- Lytton opted for the policy of Free Trade. He put an end to tariffs on 29 Articles, including Sugar, Wood-logs and drill and heavy machinery.
- In economic matters, He followed the Policy of Financial Devolution. He transferred some rights to Provincial governments such as, the rights to collect Land Revenue, Irrigation tax, etc. He also transferred matters of Law and Order, General Administration etc.
- Sir John Strachey was the Member of Finance of the Viceroy's council.
- Royal Titles Act, 1876 was introduced under the tenure of Lord Lytton. Under this act, The Queen of Britain, Victoria I, was declared as the Empress of India.
- The Great famine of 1876 occurred during Lytton's tenure. This famine lasted for nearly two years. This was also commonly known as the Madras Famine. It covered the area of approximately 257,000 square miles. It extended from Madras to Bombay, Mysore, Hyderabad, Punjab and some parts of central India.
- Lord Lytton appointed the Famine Commission in 1878. He established Famine Funds in each province to provide aid.
- The Vernacular Press Act was implemented under the 9th Article of the Act of 1878. It was also known as "The Act for the better control of Publication in Oriental Languages". Anyone who was found convicted for breaking the laws, they were punished or Penalised or both.
- Sir Erskine Perry, a member of India Council, called this act "Retrograde and Ill-conceived".

- Indian Arms Act was introduced under the 11th Article of the Act of 1878. Under this act, it was prohibited to carry or trade Arms without license. If found guilty, Convict had to serve 3 years' jail sentence or Penalty or both.
- What was wrong with this act, was that only Indians came under the provisions of this Act. Europeans, Anglo-Indians and officers of high ranks did not come under this Law.
- Lytton introduced the Statutory Civil Services in 1879-80. This Act enabled the government to fill 1/6th of total vacancies among the blue-blooded Indians, i.e. the Aristocratic Indian families.
- The maximum age of eligibility of Indians for appearing in I.C.S. reduced to 19 years from 21 years. This Examination was only conducted in London.
- The Second Anglo-Afghan War was waged during Lord Lytton's tenure.

लॉर्ड लिटन के अधीन भारत का प्रशासन, (1876-1880) :

- लॉर्ड लिटन को 1876 में बेंजामिन डिजरायली की रूढ़िवादी सरकार द्वारा भारत के प्रशासन हेतु वायसराय के पद पर नियुक्त किया गया।
- लिटन ने मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया। इसके तहत लॉर्ड लिटन ने 29 वस्तुओं पर से कर समाप्त कर दिया, जिसमें चीनी, लठ्ठे एवं भारी मशीनरी का सामान भी शामिल था।
- आर्थिक मामलों में, उन्होंने वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का पालन किया। उन्होंने कुछ अधिकारों को प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित किया जैसे कि, भूमि राजस्व इकट्ठा करने के अधिकार, सिंचाई कर, आदि। उन्होंने कानून और व्यवस्था, सामान्य प्रशासन आदि के मामलों को भी स्थानांतरित कर दिया।
- सर जॉन स्ट्रेची वायसराय की परिषद के वित्त सदस्य थे।
- राजकीय उपाधि अधिनियम, 1876 को लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पेश किया गया था। इस अधिनियम के तहत, ब्रिटेन की रानी, विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में घोषित किया गया था।
- 1876 का अकाल लिटन के कार्यकाल में घटित हुआ। यह अकाल लगभग दो वर्षों तक रहा। यह आमतौर पर "मद्रास अकाल" के रूप में भी जाना जाता था। इसने लगभग 2,57,000 वर्ग मील के क्षेत्र को अपने ग्रास में ले लिया। यह मद्रास से लेकर बॉम्बे, मैसूर, हैदराबाद, पंजाब और मध्य भारत के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था।
- लॉर्ड लिटन ने 1878 में अकाल आयोग की नियुक्ति की। उन्होंने सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्येक प्रांत में अकाल कोष की स्थापना की।
- भारतीय स्थानीय भाषा अधिनियम को 1878 के अधिनियम के 9 वें अनुच्छेद के तहत लागू किया गया था। इसे " प्राचीन भाषाओं में प्रकाशन के बेहतर नियंत्रण के लिए अधिनियम" के रूप में भी जाना जाता था। जो भी कानून तोड़ने के लिए दोषी पाए गए, उन्हें दंडित किया गया या जुर्माना लगाया गया या दोनों सजा दी गई।
- भारत परिषद के सदस्य सर एस्किन पेरी ने इस अधिनियम को "प्रतिगामी तथा असंगत" कहा।
- भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1878 के अधिनियम के 11 वें अनुच्छेद के तहत पेश किया गया था। इस अधिनियम के तहत, बिना लाइसेंस के शस्त्र रखना या हथियारों का व्यापार करना प्रतिबंधित था। यदि दोषी पाया जाता, तो अपराधी को 3 साल की जेल की सजा या जुर्माना या दोनों की सजा काटनी होती थी।
- इस अधिनियम में सबसे बड़ा दोष यह था कि केवल भारतीय इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत आए थे। यूरोपीय, एंग्लो-इंडियन और उच्च रैंक के अधिकारी इस कानून के तहत नहीं आते थे।

- लिटन ने 1879-80 में वैधानिक सिविल सेवा की शुरुआत की। इस अधिनियम ने सरकार को उच्च कुल वाले भारतीयों, यानी कुलीन भारतीय परिवारों के द्वारा कुल रिक्तियों का 1/6 वां स्थान भरने में सक्षम बनाया।
- I.C.S. परीक्षा में उपस्थित होने के लिए भारतीयों की पात्रता की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। यह परीक्षा केवल लंदन में आयोजित की गई थी।
- दूसरा एंग्लो-अफगान युद्ध लॉर्ड लिटन के कार्यकाल के दौरान हुआ था।